

DIGITAL ADDRESSABLE SYSTEMS (DAS) AUDIT REGULATORY OVERVIEW

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) often publishes consultation papers related to regulatory matters, and the Consultation Paper on Audit Related Provisions of Interconnection Regulations, 2017 and Digital Addressable Systems (DAS) Audit Manual addresses the auditing framework and the effectiveness of compliance with interconnection regulations for digital television services in India.



डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) ऑडिट विनियामक अवलोकन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अक्सर विनियामक मामलों से संबंधित परामर्श पत्र प्रकाशित करता है, और इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) ऑडिट मैनुअल पर परामर्श पत्र भारत में डिजिटल टेलीविजन सेवाओं के लिए ऑडिटिंग ढांचे और इंटरकनेक्शन विनियमों के अनुपालन की प्रभावशीलता को संबोधित करता है।

BACKGROUND AND CONTEXT

- ◆ **Interconnection Regulations, 2017:** These regulations govern the relationships between broadcasters, multi-system operators (MSOs), and local cable operators (LCOs). They regulate how channels are shared, priced, and made available to consumers.
- ◆ **Digital Addressable Systems (DAS):** The transition to DAS allowed for encrypted and addressable TV services, ensuring that subscribers only receive the channels they pay for. Audits ensure transparency and compliance.

OBJECTIVES OF THE CONSULTATION PAPER

- ◆ **Audit Mechanism Review:** It seeks feedback on improving the auditing processes for interconnection agreements, focusing on whether the current framework is sufficient to ensure transparency in revenue sharing between stakeholders.
- ◆ **Compliance Issues:** The paper looks into existing compliance gaps in implementing the Interconnection Regulations, such as revenue misreporting and adherence to service quality standards.
- ◆ **Proposed Changes:** TRAI may suggest amendments

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- ◆ **इंटरकनेक्शन विनियम, 2017:** ये विनियम प्रसारकों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएमओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। वे विनियमित करते हैं कि चैनल कैसे साझा किये जाते हैं, मूल्य निर्धारण किया जाता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है।
- ◆ **डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस):** डीएएस ने एन्क्रिप्टेड व एड्रेसेबल टीवी सेवाओं की अनुमति दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ ग्राहकों को वे चैनल ही मिलें जिनके लिए वे भुगतान करते हैं। ऑडिट पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

परामर्श पत्र के उद्देश्य

- ◆ **ऑडिट तंत्र की समीक्षा:** यह अंतरसंयोजन समझौतों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं में सुधार के बारे में फीडबैक मांगता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या मौजूदा ढांचा हितधारकों के बीच राजस्व साझाकरण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।
- ◆ **अनुपालन मुद्दे:** यह दस्तावेज इंटरकनेक्शन विनियमों के कार्यान्वयन में मौजूदा अनुपालन अंतरालों, जैसे राजस्व की गलत रिपोर्टिंग और सेवा गुणवत्ता मानकों के पालन पर गौर करता है।

to the auditing procedures in the DAS Audit Manual, refining how audits are conducted, and how non-compliance should be addressed.

KEY PROVISIONS BEING REVIEWED

- ◆ **Revenue Audits:** Ensuring that MSOs and LCOs accurately report revenue to broadcasters.
- ◆ **Subscriber Base Audits:** Verifying that reported subscriber numbers match the actual numbers, which is crucial for pricing agreements and revenue sharing.
- ◆ **Technical Audits:** Assessing if DAS systems and encryption methods are functioning as per the regulations, ensuring no unauthorized access or piracy.
- ◆ **Audit Frequency and Independence:** Discussing how often audits should take place and ensuring that auditors are impartial and competent.



STAKEHOLDER FEEDBACK

- ◆ TRAI invites stakeholders like broadcasters, MSOs, LCOs, and consumers to submit comments on issues such as:
 - The need for better compliance mechanisms.
 - Challenges in implementing the current audit guidelines.
 - Suggestions for enhancing the audit manual's scope and rigor.

EXPECTED OUTCOMES

Based on feedback, TRAI may revise the *Interconnection Regulations, 2017* and the *DAS Audit Manual* to include stricter compliance checks, more transparent reporting, and enhanced technical standards for audits.

SUMMARY OF THE ISSUES FOR CONSULTATION AUDIT SCOPE AND PROCEDURES

- ◆ **Adequacy of Existing Audit Framework:** Are the current audit provisions in the Interconnection Regulations and DAS Audit Manual sufficient? Should they be expanded or modified to better address current challenges in the broadcasting and distribution ecosystem?

- ◆ **प्रस्तावित परिवर्तन:** ट्राई डीएस ऑडिट मैनुअल में ऑडिटिंग प्रक्रियाओं में संशोधन का सुझाव दे सकता है, ऑडिट कैसे किये जाते हैं और गैर अनुपालन कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, इसे परिष्कृत करता है।

समीक्षा किये जा रहे प्रमुख प्रावधान

- ◆ **राजस्व ऑडिट:** यह सुनिश्चित करना कि एमएसओ और एलसीओ प्रसारकों को राजस्व की सही रिपोर्ट करें।
- ◆ **सब्सक्राइबर बेस ऑडिट:** यह सत्यापित करना कि रिपोर्ट की गयी सब्सक्राइबर संख्या वास्तविक संख्या से मेल खाती है, जो मूल्य निर्धारण समझौतों और राजस्व साझाकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- ◆ **तकनीकी ऑडिट:** यह आकलन करना कि क्या डीएस सिस्टम और एन्क्रिप्शन विधियां नियमों के अनुसार काम कर रही है,

यह सुनिश्चित करना कि कोई अनधिकृत पहुंच या चोरी न हो।

- ◆ **ऑडिट फ्रीक्वेंसी और स्वतंत्रता:** इस बात पर चर्चा करना कि ऑडिट कितनी बार होने चाहिए और यह सुनिश्चित करना कि ऑडिटर निष्पक्ष और सक्षम है।

हितधारकों की प्रतिक्रिया

- ◆ ट्राई प्रसारकों, एमएसओ, एलसीओ और उपभोक्ताओं जैसे हितधारकों को निम्नलिखित मुद्दों पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है:
 - बेहतर अनुपालन तंत्र की आवश्यकता
 - वर्तमान ऑडिट दिशा-निर्देशों को लागू करने में चुनौतियां
 - ऑडिट मैनुअल के दायरे और कठोरता को बढ़ाने के लिए सुझाव।

अपेक्षित परिणाम

प्रतिक्रिया के आधार पर ट्राई इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 और डीएस ऑडिट मैनुअल को संशोधित कर सकता है, ताकि संख्य अनुपालन जांच, अधिक पारदर्शी रिपोर्टिंग और ऑडिट के लिए आधुनिक तकनीकी मानकों को शामिल किया जा सके।

परामर्श के लिए मुद्दों का सारांश

ऑडिट का दायरा और प्रक्रियायें

- ◆ **मौजूदा ऑडिट ढांचे की पर्याप्तता:** क्या इंटरकनेक्शन विनियम और डीएस ऑडिट मैनुअल में मौजूदा ऑडिट प्रावधान पर्याप्त हैं? क्या उन्हें प्रसारण और वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा चुनौतियों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए विस्तारित या संशोधित किया जाना चाहिए?

- ◆ **Audit Methodology:** Is the existing audit methodology effective in uncovering irregularities, such as under-reporting of revenue or subscriber data? Should there be a standardized approach across all auditors?

FREQUENCY AND TYPE OF AUDITS

- ◆ **Audit Frequency:** Should there be a change in the frequency of mandatory audits for service providers? Is the current annual audit sufficient, or is there a need for more frequent audits or surprise inspections to ensure compliance?
- ◆ **Types of Audits:** Should the regulations differentiate between types of audits (e.g., technical, financial, compliance audits)? How should audits be prioritized based on risk factors like the size of the operator?



AUDITOR INDEPENDENCE AND COMPETENCE

- ◆ **Appointment of Auditors:** How should auditors be appointed to ensure independence? Should TRAI or another regulatory body be involved in the appointment of auditors to prevent conflicts of interest?
- ◆ **Auditor Qualifications:** What qualifications and experience should auditors possess to be eligible to perform audits in the digital broadcasting space?
- ◆ **Audit Panel Creation:** Should there be a centralized panel of TRAI-approved auditors to enhance the credibility and consistency of audits?

AUDIT REPORT STANDARDIZATION

- ◆ **Audit Report Format:** Should the format of audit reports be standardized to ensure consistency and ease of comparison across operators? If so, what specific metrics and data should be included in all audit reports?
- ◆ **Reporting Timeframes:** What should be the ideal timeframe for submitting audit reports after the completion of the audit? Should there be penalties for delayed or incomplete audit reports?

ENSURING COMPLIANCE

- ◆ **Penalties for Non-compliance:** What should be the penalties for operators failing to comply with audit

- ◆ **ऑडिट पद्धति:** क्या मौजूदा ऑडिट पद्धति राजस्व या ग्राहक डेटा की कम रिपोर्टिंग जैसी अनियमितताओं को उजागर करने में प्रभावी है? क्या सभी ऑडिटों के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए?

फ्रीक्वेंसी और ऑडिट के प्रकार

- ◆ **ऑडिट फ्रीक्वेंसी:** क्या सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य ऑडिट की फ्रीक्वेंसी में बदलाव होना चाहिए? क्या वर्तमान वार्षिक ऑडिट पर्याप्त है या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक लगातार ऑडिट या औचक निरीक्षण की आवश्यकता है?
- ◆ **ऑडिट के प्रकार:** क्या विनियमों में ऑडिट के प्रकारों (जैसे तकनीकी, वित्तीय, अनुपालन ऑडिट) के बीच अंतर होना चाहिए? ऑपरेटर कए आकार जैसे जोग्खिम कारकों के आधार पर ऑडिट को कैसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

ऑडिटर की स्वतंत्रता और योग्यता

- ◆ **ऑडिटों की नियुक्ति:** स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए? क्या हितों के टकराव को रोकने के लिए ऑडिटों की नियुक्ति में ट्राई या किसी अन्य विनियामक निकाय को शामिल किया जाना चाहिए?
- ◆ **ऑडिटों की योग्यता:** डिजिटल प्रसारण क्षेत्र में ऑडिट करने के लिए ऑडिटर के पास क्या योग्यता और अनुभव होना चाहिए?
- ◆ **ऑडिट पैनल का निर्माण:** क्या ऑडिट की विश्वनीयता और निरंतरता बढ़ाने के लिए ट्राई द्वारा अनुमोदित ऑडिटों का एक केंद्रिकृत पैनल होना चाहिए?

ऑडिटर रिपोर्ट का मानकीकरण

- ◆ **ऑडिट रिपोर्ट का प्रारूप:** क्या ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूप को मानकीकृत किया जाये, ताकि ऑपरेटरों के बीच तुलना में एकरूपता और आसानी सुनिश्चित हो सके? यदि हां, तो सभी ऑडिट रिपोर्ट में कौन से विशिष्ट मीट्रिक्स और डेटा शामिल किये जाने चाहिए?
- ◆ **रिपोर्टिंग समय-सीमा:** ऑडिट पूरा होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए आदर्श समय-सीमा क्या होनी चाहिए? क्या देरी से या आधूरी ऑडिट रिपोर्ट के लिए दंड होना चाहिए?

अनुपालन सुनिश्चित करना

- ◆ **गैर अनुपालन के लिए दंड:** ऑडिट प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले ऑपरेटरों के लिए दंड क्या होनी

provisions? Should there be stricter financial penalties or operational restrictions for non-compliance?

- ◆ **Follow-up Audits:** Should follow-up audits be mandated if issues are found during an initial audit? How should recurring non-compliance be addressed?

COST OF AUDITS

- ◆ **Audit Costs:** How should audit costs be structured and who should bear these costs? Should the cost of audits be shared between broadcasters, MSOs, and LCOs, or should one party bear the majority of the cost?
- ◆ **Audit Fee Cap:** Should there be a cap on the fees charged by auditors to prevent overcharging, and ensure the process remains affordable for smaller operators?

IMPLEMENTATION OF AUDIT FINDINGS

- ◆ **Action on Audit Findings:** What measures should be taken based on audit findings? Should there be a formal process for rectifying issues uncovered during audits, and how should these measures be enforced by TRAI or other authorities?
- ◆ **Public Disclosure of Audit Outcomes:** Should audit outcomes, especially in cases of significant non-compliance, be publicly disclosed to ensure transparency?

SUBSCRIBER MANAGEMENT SYSTEM (SMS) AND CONDITIONAL ACCESS SYSTEM (CAS)

- ◆ **System Integrity Audits:** Should there be mandatory audits of the SMS and CAS systems to ensure that they are functioning properly, and that operators are reporting subscriber numbers accurately?
- ◆ **Data Accuracy:** How should the accuracy of subscriber data generated by the SMS and CAS systems be verified during audits, and what methods can be used to cross-check these numbers?

ENSURING EFFECTIVE REGULATION IN DAS

- ◆ **Clarity in Regulations:** Are the current regulations governing audits of DAS and interconnection agreements clear, or is there a need for more explicit guidelines? What ambiguities need to be addressed to improve compliance?
- ◆ **Best Practices:** Should TRAI adopt international best practices in auditing for digital addressable systems to improve the effectiveness of audits in the Indian context?

चाहिए? गैर-अनुपालन के लिए क्या सख्त वित्तीय दंड या परिचालन प्रतिबंध होना चाहिए?

- ◆ **फॉलोअप ऑडिट:** यदि आरंभिक ऑडिट के दौरान कोई समस्या हो तो क्या फॉलोअप ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए? बार-बार होने वाले गैर अनुपालन को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए?

ऑडिट की लागत

- ◆ **ऑडिट लागत:** ऑडिट लागतों को कैसे संरचित करें और इन लागतों को कौन वहन करेगा? क्या ऑडिट की लागत प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के बीच साझा की जानी चाहिए, या एक पक्ष को लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करना चाहिए?
- ◆ **ऑडिट शुल्क सीमा:** क्या ऑडिटों द्वारा ली जाने वाली फीस पर कोई सीमा होनी चाहिए ताकि अधिक शुल्क न लिया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया छोटे ऑपरेटरों के लिए वहनीय बनी रहे?

ऑडिट निष्कर्षों को लागू करना

- ◆ **ऑडिट निष्कर्षों पर कार्रवाई:** ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर क्या उपाय किये जाने चाहिए? क्या ऑडिट के दौरान आये मुद्दों को सुधारने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए और इन उपायों को ट्राई या अन्य अधिकरणों द्वारा कैसे लागू किया जाना चाहिए?
- ◆ **ऑडिट परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण:** क्या ऑडिट परिणामों को विशेष रूप से गैर-अनुपालन मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रकट किया जाना चाहिए?

सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएस)

- ◆ **सिस्टम अखंडता ऑडिट:** क्या एसएमएस और सीएस सिस्टम का अनिवार्य ऑडिट होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं और ऑपरेटर सब्सक्राइबर संख्या की सही रिपोर्ट कर रहे हैं?
- ◆ **डेटा सटीकता:** एसएमएस व सीएस द्वारा सब्सक्राइबर डेटा की सटीकता को ऑडिट के दौरान कैसे सत्यापित और इन नंबरों को क्रॉस चेक के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है?

डीएस में प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करना

- ◆ **विनियमन में स्पष्टता:** क्या डीएस व इंटरकनेक्शन समझौतों के ऑडिट को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियमन स्पष्ट हैं या अधिक स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है? अनुपालन में सुधार के लिए किन अस्पष्टताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है?
- ◆ **सबसे अच्छा तरीका:** क्या ट्राई को भारतीय संदर्भ में ऑडिट की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम प्रणालियों के ऑडिट में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना चाहिए?